



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07032020-216576
CG-MH-E-07032020-216576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2020/फाल्गुन 13, 1941

No. 94]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2020/PHALGUNA 13, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 27 फरवरी, 2020

सं. टीएएमपी/5/2019-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963) 1963का (38की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई पत्तन न्यास के एसओआर (एमबीपीटी) में एक संशोधन के लिए पत्तन से प्राप्त प्रस्ताव का संलग्न आदेश के अनुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/5/2019-एमबीपीटी

मुंबई पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम:

- (i). श्री टीबालसुब्रमनियन.एस., सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(फरवरीवें दिन पारित 20 के 2010)

मुंबई पत्तन न्यास द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर (एमबीपीटी), इस प्राधिकरण ने 24 जुलाई, 2019 के अपने आदेश सं. टीएएमपी/5/2019-एमबीपीटी के तहत एमबीपीटी के दरमानों में संशोधन किया था। उक्त संशोधित एसओआर 3 सितंबर 2019 को भारत के राजपत्र में राजपत्र सं. 308 पर अधिसूचित किये गये थे।

2.1. इस संदर्भ में, एमबीपीटी ने अपने पत्र क्रमांक एफएसीसी/एसीसी/191(ख)/3791 दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को अपने अधिसूचित दरमानों में संशोधन समीक्षा के लिए अनुरोध किया है। एमबीपीटी/ द्वारा किए गए उल्लेख इस प्रकार हैं:

- (i) 24 जुलाई 2019 के आदेश के पैरा 11 (xxiv) में, यह कहा गया है कि एमबीपीटी ने यह स्थापित नहीं किया है कि पत्तन विविध पोतों के एसओआर के लिए 1000 जीआरटी के न्यूनतम स्तर का प्रस्ताव करके टोवेज और पाइलटेज के कंपोजिट प्रभार के लिए दरमानों के खंड 2.1(ख) के नीचे प्रस्तावित नोट के अनुसार निर्धारित लागत की वसूली कैसे कर पाएगा? उक्त पैरा में यह भी कहा गया है कि कंपोजिट पायलेटेज और टोवेज का न्यूनतम स्तर तय करने के कारण पत्तन को होने वाली अतिरिक्त आय, का पत्तन द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है।
- (ii) इस संबंध में, यह उल्लेख किया गया है कि जीआरटी के अनुसार प्रस्तावित नोट 'प्रभार्य प्रभार न्यूनतम 1000 जीआरटी पर लगाया जाएगा' जो प्राधिकरण द्वारा एमबीपीटी के दरमान (2004) में उल्लेखित था, जिसे टीएएमपी द्वारा 2006 में किए गए संशोधन पैरा 9 (xxix) आदेश 2006 के द्वारा हटा दिया गया था। इसलिए, यह एक नई स्थिति नहीं है और अतीत में पत्तन द्वारा लगाया जा रहा था।
- (iii) उपयोगकर्ताओं ने 2019 में एमबीपीटी के एसओआर में न्यूनतम 1000 जीआरटी की प्रस्तावित शर्त पर आपत्ति नहीं जताई है।
- (iv) पत्तन सभी पत्तन उपयोगकर्ताओं को पायलट सेवा, नौचालन और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। इसलिए, पत्तन द्वारा उपयोगकर्ताओं के अनुरोध के अनुसार, 1000 जीआरटी से कम और 1000 से अधिक जीआरटी वाले पोतों को समान सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- (v) 1000 से कम जीआरटी वाले पोत छोटे पोत होते हैं जिनके अनुसूची 2.1(ख) में निर्धारित पायलट और टोवेज-प्रभार बहुत कम होते हैं। इसलिए, 1000 जीआरटी से कम के पोतों से पायलट और टोवेज से उत्पन्न आय, किए गए व्यय के अन-अनुपातिक है।
- (vi) 2018-19 के दौरान 1000 जीआरटी से कम वाले पोतों के लिए पायलट और टोवेज सेवाओं के लिए किए गए व्यय और अतिरिक्त राजस्व का एक लागत विवरण एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
(एमबीपीटी के परिकलन से, यह देखा गया है कि 1000 से कम जीआरटी वाले पोतों के संबंध में टग के बिना पायलटेज सेवा पर किए गए व्यय रु. 26.28 करोड़ की लागत की तुलना में अनुमानित राजस्व न्यूनतम 1000 जीआरटी वाले पोत पर विचार किया जाए तो राजस्व लगभग केवल रु. 1.35 करोड़ है। इस प्रकार, न्यूनतम 1000 जीआरटी वाले पोत पर पायलट शुल्क लगाने पर विचार करने के बाद भी, रु. 24.93 करोड़ का अंतर रहता है।)
- (vii) उक्त संशोधन से अतिरिक्त आय होने की पर्याप्त संभावना नहीं है और यह केवल 91.16 लाख तक होगी।

- 2.2. उपरोक्त के आधार पर, एमबीपीटी ने इस प्राधिकरण से के लिए के लिए खंड 2.1 से नीचे नोट्स में क्रम सं. 9 पर प्रस्तावित सशर्तता शामिल करने (नोट) के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है जो खंड (क) (ग) और दोनों पर लागू होगा ताकि पत्तन को इस सेवा के लिए निर्धारित लागत, कम से कम आंशिक लागत ही सही, वसूल करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। एमबीपीटी ने यह भी कहा है कि इससे एमबीपीटी को पत्तन के अन्य सेवादारों पर ऐसी लागत प्रभारित न करने में मदद मिलेगी।
3. एमबीपीटी द्वारा 16 अक्टूबर 2019 के अपने पत्र में किए गए उल्लेखों के संबंध में, निम्नलिखित बिंदु प्रासंगिक हैं:
- (i) एमबीपीटी द्वारा दायर सामान्य पुनरीक्षण प्रस्ताव का निपटान करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा पारित 24 जुलाई 2019 के आदेश के पैरा सं. 11 (xxiv) का संदर्भ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:
- “ एमबीपीटी के दरमानों के खंड 2.1 (ख) में विविध पोतों अर्थात् ऑफ शोर आपूर्ति पोतों, सर्वेक्षण वाहिकाओं और विशिष्ट सहायक वाहिकाओं, अस्थायी क्रेन, रिग पोतों, ड्रेजर्स, निर्माणधीन पोतों, टेलीग्राफ पोतों, टग्स, नावों, यात्री नौकाओं, मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर, स्वचालित बार्ज, डंबल बार्ज, लैश बार्ज, मनोरंजन-नौका, देशज यान, क्रू-बोट आदि के लिए समग्र पायलटेज और टोवेज शुल्क निर्धारित किए गए हैं। एमबीपीटी ने इस आशय का एक नोट प्रस्तावित किया है कि गतिविधियों में शामिल उपरोक्त उल्लिखित पोतों के लिए न्यूनतम 1000 जीआरटी पर, निश्चित लागत को पुनर्प्राप्त करने के लिए कंपोजिट पाइलटेज और टोवेज शुल्क लगाया जाए। एमबीपीटी ने यह स्थापित नहीं किया है कि 1000 जीआरटी का न्यूनतम स्तर तय करने से पत्तन अपनी निर्धारित लागतों की वसूली कैसे कर पाएगा। संयोजी पायलटेज और टोवेज के लिए न्यूनतम स्तर तय करने के कारण पत्तन को होने वाली अतिरिक्त आय को पत्तन द्वारा उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, प्रस्तावित नोट मान्य नहीं है। ”
- (ii) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उक्त नोट को निर्धारित नहीं करने का कारण यह था कि एमबीपीटी ने यह स्थापित नहीं किया था कि 1000 जीआरटी का न्यूनतम स्तर तय करने से पत्तन अपनी निर्धारित लागतों को कैसे वसूल करेगा और कंपोजिट पायलट और टोवेज के लेवी के लिए एक न्यूनतम स्तर तय करने से पत्तन को होने वाली अतिरिक्त आय का उल्लेख नहीं किया गया था।
- (iii) अब, पत्तन ने परिकलन के साथ स्थापित किया है जो कि 1000 से कम जीआरटी वाले पोतों के संबंध में टग के बिना पायलट सेवा पर किए गए व्यय और 1000 जीआरटी के न्यूनतम पोत पर उत्पन्न होने वाले राजस्व पर विचार करते हुए अंतर रु.24.93 करोड़ का अंतर बिना पूरा किए रह जाएगा। पत्तन द्वारा उक्त संशोधन से उत्पन्न अतिरिक्त आय की संभावना रु. 91.16 लाख प्रति वर्ष की दर से की गई है।
- (iv). स्मरणीय है कि एमबीपीटी के सामान्य संशोधन आदेश में, रु.39.02 करोड़ का अंतर, पत्तन द्वारा बिना वसूली के छोड़ दिया गया है। इस प्रकार, प्रस्तावित नोट की शुरुआत से होने वाले रु.91.16 लाख के अतिरिक्त राजस्व की मंजूरी दी जाएगी, जो राजस्व के अंतर को कम करेगा।
- (v) उपर्युक्त प्रस्तुतियाँ के मद्देनजर और यह देखते हुए कि प्रस्तावित निर्धारण एमबीपीटी द्वारा दायर सामान्य संशोधन प्रस्ताव का एक हिस्सा है, जिसे हितधारकों के साथ परामर्श से किया गया है और चूंकि किसी भी उपयोगकर्ता ने उस समय एमबीपीटी के सामान्य संशोधन प्रस्ताव से संबंधित कार्यवाही में प्रस्तावित संशोधन पर आपत्ति नहीं जताई, यह प्राधिकरण अपने सामान्य पुनरीक्षण प्रस्ताव में एमबीपीटी द्वारा प्रस्तावित नोट के शामिल किए जाने को अनुमोदित करने का इच्छुक है।

(vi) इस प्राधिकरण के पारित आदेश सामान्यतराजपत्र : में अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद से, प्रभावी रूप से लागू होते हैं, जब तक कि अन्यथा अलगअलग व्यवस्था विशेष रूप से संबंधित - टैरिफ आदेशों में उल्लिखित न हो। तदनुसार, प्रस्तावित संशोधन, भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद संभावित रूप से लागू होगा।

4.1 परिणामतः, और ऊपर दिए गए कारणों से और सामूहिक सोच विचार-के आधार पर, यह प्राधिकरण निम्नलिखित नोट को 'खंडइसके मौजूदा एसओआर में कंपोजिट पाइलटेज और टोवेज शुल्क - 2.1 ' के तहत सामान्य नोट के रूप में शामिल करने के लिए करने की मंजूरी देता है।

“(9).जीआरटी के अनुसार लगाए जाने वाले प्रभार न्यूनतम न्यूनतम1000 .जीआरटी पर लगाए जाएंगे”

4.2 एमबीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह अपने दरमानों में उपरोक्त प्रावधान को उपयुक्त रूप से शामिल करे।

4.3 भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद, उक्त प्रविष्टि प्रभावी हो जाएगी और इसकी वैधता एमबीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता के साथ सह कार्यान्वित-रहेगी।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./480/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, 27th February, 2020

No. TAMP/5/2019-MBPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for an amendment to its SOR, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/5/2019-MBPT

Mumbai Port Trust

Applicant

QUORUM:

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 20th day of February 2020)

Based on the proposal filed by Mumbai Port Trust (MBPT), this Authority *vide* its Order No. TAMP/5/2019-MBPT dated 24 July 2019 had revised the Scale of Rates (SOR) of MBPT. The said revised SOR was notified in the Gazette of India on 3 September 2019 *vide* Gazette no. 308.

2.1. In this context, the MBPT *vide* its letter No. FA/ACC/191(B)/3791 dated 16 October 2019 has requested for review/ amendment in its notified Scale of Rates. The submissions made by MBPT are as follows:

- (i) In para 11 (xxiv) of the Order dated 24 July 2019, it is stated that the MBPT has not established how fixing the minimum level of 1000 GRT will enable the port to recover the fixed cost on the note proposed below Section 2.1 (B) of the SOR for Composite Towage and Pilotage charges for Miscellaneous vessels. The said para also states that the additional income arising to the port on account of fixing a minimum level of composite pilotage and towage is not captured by the port.
- (ii). In this regard, it is submitted that the proposed note 'Charges leviable according to GRT will be levied on a minimum of 1000 GRT' existed in MBPT SOR (2004) which was deleted by

TAMP in 2006 revision (para 9 (xxix) of TAMP order 2006). Hence, this is not a new conditionality and was being levied by the port in the past.

- (iii) Users have not objected to the proposed conditionality of minimum 1000 GRT in the SOR of MBPT in 2019.
- (iv) The port provides pilotage service, navigational aids and other facilities to all port users. Hence, as per the request of port users, similar services are provided to vessels of less than 1000 GRT and more than 1000 GRT.
- (v) The vessels having less than 1000 GRT are small vessels of which Pilotage and Towages charges prescribed at schedule 2.1 (B) are much lower. Hence, income generated from pilotage and towage from vessels of less than 1000 GRT is disproportionate to the expenditure incurred.
- (vi) A Cost statement of working of the expenditure incurred and additional revenue for Pilotage and Towage services for vessels having less than 1000 GRT during 2018-19 is furnished by MBPT.

(From the workings furnished by MBPT, it is seen that as against the expenditure incurred on the Pilotage service without tug in respect of less than 1000 GRT vessels to the tune of ₹ 26.28 crores, the revenue that is estimated to be generated by considering a minimum of 1000 GRT of vessel is about ₹ 1.35 crores only. Thus, even after considering levy of pilotage charges on minimum 1000 GRT, there is a gap of ₹ 24.93 crores.)

- (vii). Additional income likely to be generated by the said modification is not substantial and is only to the tune of ₹ 91.16 lakhs.

2.2. Based on the above, MBPT has requested this Authority to grant approval for the proposed conditionality (note) to be incorporated at Sr. 9 of notes below Section 2.1 applicable to both the sections (A) & (B) so as to enable the port recover the fixed costs incurred for this service, at least partially. The MBPT has also stated that this would also help MBPT to avoid loading such cost on other servicers of the port.

3. With regard to the submissions made by MBPT vide its letter dated 16 October 2019, the following points are relevant:

- (i) Reference is drawn to para no. 11(xxiv) of the Order dated 24 July 2019 passed by this Authority disposing of the general revision proposal filed by MBPT, which is reproduced below:

“Section 2.1 (B) of the SOR of MBPT prescribes composite pilotage and towage charges for Miscellaneous vessels viz., Off Shore Supply Vessels, Survey vessels and specific support vessels, floating cranes, rig vessels, dredgers, vessels under construction, telegraph vessels, Tugs boats, Passenger boats, Fishing trawlers, Self-propelled Barges, dumb barges, lash barges, pleasure yacht, country crafts, crew boats, etc. The MBPT has proposed a note to the effect that composite pilotage and towage charges for the above referred vessels shall be levied at minimum of 1000 GRT in order to recover the fixed cost involved in the activity. The MBPT has not established how fixing the minimum level of 1000 GRT will enable the port to recover its fixed costs. The additional income arising to the port on account of fixing a minimum level for levy of composite pilotage and towage is not seen to have been captured by the port. Hence, the introduction of the proposed note is not acceded to.”
- (ii) As brought out above, the reason for not prescribing the said note was that the MBPT had not established how fixing the minimum level of 1000 GRT will enable the port to recover its fixed costs and had not captured the additional income arising to the port on account of fixing a minimum level for levy of composite pilotage and towage.
- (iii) Now, the port has established with workings that considering the expenditure incurred on the Pilotage service without tug in respect of less than 1000 GRT vessels and the revenue that is estimated to be generated by considering a minimum of 1000 GRT of vessel, a gap of ₹ 24.93 crores will be left uncovered. The Additional income likely to be generated by the said modification has been quantified by the port at ₹ 91.16 lakhs per annum.
- (iv) It may be recalled that in the general revision Order of MBPT, a gap of ₹ 39.02 crores, has been left uncovered by the Port. Thus, the additional revenue of ₹ 91.16 lakhs arising out of introduction of proposed note (to be) approved, would get subsumed in the revenue gap.
- (v) In view of the above submissions and considering that the proposed prescription formed part of the general revision proposal filed by MBPT which was consulted with the stakeholders

and since no user had objected to the proposed modification in the proceedings relating to the general revision proposal of MBPT at that point in time, this Authority is inclined to approve insertion of the note, as proposed by the MBPT, in its general revision proposal.

- (vi) Orders passed of this Authority generally comes into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. Accordingly, the proposed modification shall come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Notification of this Order in the Gazette of India.

4.1 In the result, and for the reasons give above, and based on the collective application of mind, this Authority approves insertion of the following note as common note No. (9) under Section 2.1 - Composite Pilotage and Towage charges, in its existing SOR:

“(9). Charges leviable according to GRT will be levied on a minimum of 1000 GRT.”

4.2 The MBPT is advised to suitably incorporate the above provision in its Scale of Rates.

4.3 The said insertion shall come into effect after expiry of 30 days from the date of Notification of this Order in the Gazette of India and its validity shall remain co-terminus with the validity of the existing Scale of Rates of MBPT.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./480/19]